

ing either rural or urban areas specifically. Thus it is not feasible to estimate how much of past plan expenditure has gone into the villages. It is regretted that no meaningful estimate of per capita development outlay on villages can be proposed, either State-wise or on all India basis.

आपात स्थिति के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित नाटक और रूपक

3047. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित कितने नाटकों और रूपकों को वास्तव में अति उत्तम होने की संज्ञा दी जा सकती है;

(ख) आपात स्थिति के दौरान आकाशवाणी में प्रशंसनीय काम करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार ने उन्हें उनके काम के लिए क्या प्रोत्साहन दिया था; और

(घ) क्या मंत्रालय में ऐसा उत्तम कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने की कोई पद्धति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल गण अडवाणी) : (क) आपात स्थिति के दौरान अर्थात् जून, 1975 से मार्च, 1977 तक, आकाशवाणी ने लगभग 8,000 नाटक और इतनी ही संख्या में रूपक उन विभिन्न भाषाओं में प्रसारित किये जिनमें आकाशवाणी के केंद्रों से कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों की अवधि 5 मिनट और 50 मिनट के बीच थी।

इनमें से 9 नाटकों को और 7 रूपकों को "आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार" दिये गये थे। दो कार्यक्रमों को एशिया पैसिफिक

ब्राडकास्टिंग यूनियन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिये गये थे। पुरस्कार स्क्रिप्ट और कार्यक्रम तैयार करने की श्रेष्ठता के आधार पर दिये गये।

किसी भी कार्यक्रम को अति उत्तम होने की संज्ञा नहीं दी गई।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम दिये हुए हैं जिनको 1975 और 1976 में आकाशवाणी पुरस्कार और उसी अवधि के दौरान एशिया पैसिफिक ब्राडकास्टिंग यूनियन के पुरस्कार प्राप्त हुए। [ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल टी-1295/77]

(ग) इन व्यक्तियों को जो एक मान प्रोत्साहन दिया जाता है वह "आकाशवाणी पुरस्कार" है जैसा कि उक्त (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दिया हुआ है।

(घ) जी, हां। "आकाशवाणी पुरस्कार" हर वर्ष दिये जाते हैं।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का विद्युतीकरण

3048. श्री श्यामलाल धुबे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के बारे में सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो माण्डला (मध्य प्रदेश) के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :

(क) पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम आसान और उदार शर्तों पर राज्य विजली बोर्डों को ऋण देता है ।

(ख) मण्डला जिले में ग्राम विद्युतीकरण की 804 लाख रुपये की ऋण सहायता की दो स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं । इनमें से 172 गांवों के विद्युतीकरण की तथा 1700 पम्पसैटों के ऊर्जन की परिकल्पना है । ये स्कीमें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इनके अलावा, चालू वर्ष के दौरान लिस्ट सिचाई स्कीमों के अन्तर्गत भी नौ गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा ।

(ग) बिजली का विस्तार कृषकों और उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न भार विकास पर निर्भर होगा ।

Precision guided devices

3049. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the revolution in military hardware manufacture created by the introduction of Precision Guided Devices;

(b) if so, whether our defence production is tuned to the needs of using precision guided devices; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Defence Production sector is making certain guided missiles at present and is gearing itself to meet future

requirement of the Services. It would not be in the public interest to disclose details.

Designing and manufacture of electron Microscope

3050. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether indigenous capacity to design and manufacture electron microscopes exists in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). A prototype scanning electron microscope has been assembled at the Central Scientific Instruments Organisation (CSIO) Chandigarh in collaboration with a number of other laboratories. The Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI), Pilani has developed all the associated electronics including the scan generator and power supplies, the Bhabha Atomic Research Centre (BARC) has contributed towards the electron gun; the National Physical Laboratory (NPL), New Delhi has designed the vacuum systems; while the systems hardware including lens design and assembly of the Unit has been done at the CSIO, Chandigarh. The Banaras Hindu University (BHU), which has a sophisticated electron-optical bench, was also involved in the work on lens design. Scientists from BARC and the Indian Institute of Technology, Delhi have acted as consultants to the project. The prototype electron microscope will be available for user trials by the end of 1977. The Central Electronics Ltd. a public sector corporation, has been given the responsibility for development of production technologies for the Scanning Electron Microscope resulting from this development project. To decrease the time between R. & D. and final production, the Central Electronics Ltd. has been associated with this project right from the beginning.